भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2962
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

2962. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पीपीपी मॉडल को मनरेगा के मौजूदा ढांचे में किस प्रकार एकीकृत किया जाएगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं कि ऐसी भागीदारी से ग्रामीण गरीबों और सीमांत समुदायों को रोजगार प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से समझौता न हो;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के संबंध में कामगार संघों और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है; और

(ङ) क्या मनरेगा परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल को लागू करने की कोई समय-सीमा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं , प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत , मजदूरी और प्रशासनिक घटक के भुगतान पर होने वाला 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन

किया जाता है, जबकि सामग्री घटक पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****